श्री रामसेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मेरा निवेदन यह है कि जब फ़ाक्कर फ़ैंडशिप ख़रीदने की व्यवस्था हो रही थी, तब सरकार की तरफ़ से यह कहा गया था कि "फ़ाक्कर फ़ैंडशिप विल डिस्प्लेस डैकोटा प्लेन्ज"। अब यह कहा जा रहा है कि जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐव्रो–748 को ख़रीद लेंगे, तब डैकोटाज चले जायेंगे। ऐसा मालूम होता है कि सरकार को डैकोटाज़ को रखना है और आई० ए० सी० को नुकसान से ही चलाना है, वर्ना पहली बात को अमल मे लाने के लिए काम होना चाहिए था।

डा० कर्ण सिंह : आई० ए० सी० चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके, डकोटाज़ रिप्लेस हो। इस मे दो विचार नही हो सकते हैं, क्योंकि डैकोटाज़ से हमे कोई लाभ नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि डैकोटाज को किस प्रकार रिप्लेस किया जाये। हम ने पिछले साल तीन फ़ाक्कर फ्रेंडशिप खरीदे है। और दूसरे एव्रो है, जो हमारे अपने देश मे बन रहे है। जब हमे ये दोनो प्रकार के विमान मिल जायेंगे, तब हम डैकोटाज को रिप्लेस करेंगे।

अपीजे शिपिंग कम्पनी

*84. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 1 दिसम्बर, 1966 को अपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे मे हुई आधे घंटे की चर्चा के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपीजे शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध, जिसने सरकार को धोखा देने का प्रयत्न किया था, कोई कानूनी कार्यवाही की है ;

(ख) क्या अन्य सरकारी विभागों को इस शिपिंग कम्पनी के साथ सरकारी स्तर पर कोई भी सम्बन्ध न रखने की सलाह दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). No such action has been taken so far. The matter is, however, being considered further by the Government.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अब सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है और मेरे प्रश्न की सूचना मिलने के बाद वह इस बारे मे सोचने लगी है। लेकिन यह मामला बहुत पुराना है। मैं पाटिल साहब के बयान मे से केवल दो जुमले पढ़ता हू। उन्होने कहा है :

> "Referring to the SSP Leader's allegation of Shri Patil's complicity in the shortfall of rice imports from Burma during 1962 when he was the Union Food Minister, Shri Patil said, 'It is utter nonsense. Nothing of that type happened'. The entire matter had been disposed of at the level of the Under Secretary."

यह मैं 11 दिसम्बर, 1966 से भारत ज्योति से पढ़ रहा हू। आगे पाटिल साहब कहते है :

> "The Under Secretary of the Food Ministry had received a report that on one of the ships some empty gunny bags were being transported in place of rice bags. As soon as this report was received, the official took appropriate action at his level. The matter did not come up to the level of even the Deputy Secretary."

हम लोग सितम्बर महीने से इस मामले का पीछा कर रहे हैं। फिर लोक सभा का जो

जाड़े का सत्र हुआ, उसमें काले धंधे की बहस हुई। उसमें भी सरकार के द्वारा गलतबयानी और असत्य-भाषण किया गया। अमीचन्द प्यारेलाल कम्पनी के बारे में—यह जहाजरानी कम्पनी उसी की है—कई मामले आए थे। अभी अभी कानून मंत्रालय ने उसको माफी प्रदान करने का काम किया है। इस बारे में एक अल्प-सूचना प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मंत्री महोदय उसके लिए तैयार नही हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस कम्पनी के द्वारा केन्द्रीय सरकार के साथ चार-सौ-बीसी करने का प्रयास किया गया था—यह श्री गोविन्द मेनन ने स्वय पिछली बार कहा था—तो अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यो नही की गई है और उसको काली सूची मे क्यो नही डाला है। 1963 मे एक दफ़ा उसको काली सूची मे डाला गया था, लेकिन बाद मे उसको वापस ले लिया गया। इस तरह कैसे चलेगा? मतदाताओ को गुमराह करने के लिए पाटिल साहब ने मेरे खिलाफ मुकदमा चलाने की धमकी दी थी। अब सारी बाते निकल रही है। (*Interruption.*)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य लेक्चर दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं?

श्री मधु लिमये : चुप बैठो, नही तो आप की भी वही दुर्गति होगी, जो पाटिल साहब की हुई है।

Shri Annasahib Shinde: I have already submitted that the matter is being further considered. The Ministry of Iron and Steel had issued an order banning transactions with Messrs Surendra Overseas (Private) Ltd. in May, 1966. But against this order, the firm and its allied concerns filed a writ petition in the Calcutta High Court, and the Calcutta High Court has subsequently issued a stay order not to implement this order. We are examining the implications and seeing whether we can proceed in this matter. I have already stated in the main answer that we are examining it further in all its implications.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब यह मामला अदालत में आ गया है, इसलिए क्या मंत्री महोदय इससे सम्बन्धित सब काग़ज़ात आपको दिखाकर, आप से बात करके, सदन के टेबल पर रखेंगे, जिससे समूचे सदन को और देश को सत्य बातों का पता लगे, क्योंकि इस मुकदमे का इस्तेमाल मेरी जुबान को बन्द करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए किया गया है, इसलिए यह जरूरी है कि इससे सम्बन्धित वे सारे काग़ज़ात जो सरकारी फाइलो मे है, आपको दिखाकर सदन के पटल पर रखे जायें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): जैसा कि अभी मंत्री ने बताया है, यह प्रश्न आने के बाद मैंने इस मसले को देखा और देखने के बाद मैने मुनासिब समझा कि इसको ठीक तरह से देखकर इस बात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि इस बारे मे हम क्या कार्यवाही कर सकते है और इसीलिए यह जवाब दिया गया है कि इस मामले को जल्दी ही कानून मंत्रालय के पास भेजकर, उसको दिखाकर, यह देखा जाये कि हम कानूनी तरीके से या विभागीय तरीके से क्या कार्यवाही कर सकते है। यह मामला किसी कचहरी मे नही है। मंत्री ने जिस सम्बन्ध में कचहरी का जिक्र किया है, वह इस मालिक के किसी अन्य कम्पनी के सम्बन्ध मे है, जो कि अलग है।

श्री मधु लिमये : मैं जानता हू। आप अपने मंत्रियो को सिखाया करे।

Shri Annasahib Shinde: I was absolutely clear

श्री जगजीवन राम : यह मामला अभी किसी कचहरी मे नही है, क्योंकि कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई है। मैं जल्दी ही इस बारे मे कानून मंत्रालय से राय लेना चाहता हूं कि हम क्या कानूनी कार्यवाही या विभागी कार्यवाही कर सकते है।

Shri S. M. Banerjee: The hon. Food Minister is aware that this was one of the scandals which has cost Shri S. K. Patil his job. May I know whether after seeing all the papers, the hon. Minister will refer the matter either to the CBI or to the CIB for a fuller inquiry, because we have information that not only Shri S. K. Patil but many senior members are involved in this particular deal?

Shri Jagjiwan Ram: I do not think that that would be necessary. The only question is whether on the material that is available and the allegations that have been made, some legal action can be taken against the party or some departmental action can be taken. Therefore, as I have stated already, I shall consult the Ministry of Law as to whether legal or departmental action can be taken and if so, how soon it can be taken.

Shri Surendranath Dwivedy: I understood from the reply of the Minister that they are consulting legal experts and taking legal advice as to whether any legal action could be taken But it is fairly established that this company cheated Government. What prevented Government from blacklisting this very company without any delay? That could be done easily. Why have not Government done it yet?

Shri Jagjiwan Ram: The hon. Member has not listened to the hon. Minister of State. When that action was taken against another concern of the same company, it was taken to the High Court. Therefore, perhaps as a matter of abundant caution, that step was not taken. But we are going to examine the matter very carefully.

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विभागीय कार्यवाही का जिक्र किया कि वह गृह मंत्रालय से बातचीत करके विभागीय कार्यवाही भी करेंगे और दूसरी कार्यवाही भी करेंगे तो विभागीय कार्यवाही जो होगी क्या उसका असर अपीजे कम्पनी पर भी पड़ेगा या सम्बन्धित अधिकारियों पर ही पड़ेगा और यदि केवल सम्बन्धित अधिकारियों पर ही पड़ेगा तो अपीजे पर क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : विभागीय कार्यवाही का असर दोनो पर ही पड़ सकता है

Shri K. Lakkappa: The hon. Minister stated that action will have to be taken and they are considering it. In view of the seriousness of the matter, I want to know whether legal action is contemplated under the Penal Code or only under the Civil Procedure Code. Here is a case of a company cheating Government and such a case comes under the Penal Code. Is the Government contemplating action under the Penal Code?

Shri Annasahib Shinde: Whatever action is suggested by the the legal experts or the Law Ministry, that will be taken.

Shri D. N. Tiwary: Are Government aware that this whole matter was referred to the Vigilance Commissioner for his opinion as to naming the company and banning it from further contracts with government departments, and the Commissioner was of the opinion that as no action was taken against the officer concerned, no action lay against the firm? May I know whether any action has been taken against the concerned officer?

Shri Jagjiwan Ram: I shall look into this aspect.

Shri Hem Barua: In view of the fact that the Apeejay Shipping company has built up an empire of industrial interests by deceiving Government on many an occasion as also the fact that it is harbouring Pakistani nationals who are actively engaged

in anti-Indian activities, may I know from the Deputy Prime Minister whether he is prepared to institute a commission of inquiry to go into the activities of this company? If he is not prepared to do so, is it because of the fact that this Appejay Shipping company in Calcutta alone gave 20 jeeps and Rs. 4 lakhs to the Congress election fund?

An hon Member: An insinuation

Shri Hem Barua: He has not replied.

Mr. Speaker: How much money has been given by whom and for which party—I do not think they have got the statistics.

Shri Surendranath Dwivedy: The first part could be answered

Mr Speaker: He says he does not know

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): If the information is sent to me, I shall certainly make an enquiry.

Shri V Krishnamoorthi: The hon Minister in his reply stated that he is consulting the concerned departments as to whether legal or departmental action could be taken Is there any existing contract between Government and the company? If so, will Government immediately terminate it pending examination whether legal or departmental action could be taken?

Shri Annasahib Shinde: I do not think there is any existing contract But it appears that the firm still continues to carry rice from Burma to India? Even that will be examined

Shri Manubhai Patel: Government has found that there was something wrong with the company and it has to be legally examined. Why do they not stop all dealings with this company?

Shri Annasahib Shinde: As I submitted already, this also will be examined.

International Tourist Year

+

*88. **Shri R. Barua:**
Shri C. C. Desai:

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up some programme to celebrate 1967 as the International Tourist Year, and

(b) if so, the broad details of the programme chalked out in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* LT-110/67]

Shri R Barua: Have the Government made an assessment of our requirements on tourist beds in hotels and in view of that assessment do they propose to provide sufficient accommodation in the near future?

Dr Karan Singh: An assessment has been made of the hotel requirements 1200 beds are expected to be made available through Tourist Development Corporation and 900 beds are going to be provided in the private sector by the end of this year In addition to that we hope that some other hotels in the private sector will go up I agree with the hon Member that all this will not be sufficient to meet our requirements fully

Shri R Barua May I know whether any provision has been made to cater for tourists of moderate means?

Dr Karan Singh: Yes Sir, these hotels which are being envisaged under the scheme are of various classes ranging from 3 star to 5 star

Shrimati Lakshmikanthamma: May I know whether there is any programme of connecting different tourist centres by air?

Dr Karan Singh: Many tourist centres are already connected by air and we are thinking of connecting other